# अध्याय II
# अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन एवं कार्य-निष्पादन

## समेकित परिचालन[1]

2.1 बैंकों के तुलन-पत्रों में वर्ष 2011-12 से हो रही वृद्धि में कमी वर्ष 2014-15 में भी जारी रही। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की आस्तियों की वृद्धि में नरमी का मुख्य कारण 10 प्रतिशत से नीचे के ऋणों और अग्रिमों में उत्साहहीन वृद्धि है (चार्ट 2.1)। निवेश की वृद्धि में भी मामूली कमी आई है। ऋण वृद्धि में कमी औद्योगिक वृद्धि में गिरावट, कॉरपोरेट की आय में कमतर वृद्धि और बढ़ते अशोध्य ऋण तथा अभिशासन संबंधी मामलों की पृष्ठभूमि में बैंकों की जोखिम विमुखता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता के कारण, कॉरपोरेट ने अपनी वित्त-पोषण आवश्यकताओं के एक भाग की पूर्ति के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), कॉरपोरेट बांड और वाणिज्यिक पत्रों जैसे अन्य स्रोतों का भी सहारा लिया। देयता पक्ष में, जमा और उधार की वृद्धि में भी भारी गिरावट आई। बैंक-समूह वार, वर्ष 2014-15 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ऋण वृद्धि में कमी पाई गई; हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) ने उच्चतर ऋण वृद्धि दर्ज की है।

### *कासा जमाराशियां*

2.2 चालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियों में बचत जमाओं में गिरावट के कारण मामूली वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप समग्र जमा वृद्धि में कमी पाई गई (चार्ट 2.2)। बैंक-समूह वार, पीएसबी की कासा जमाराशियों में गिरावट दर्ज की गई जबकि पीवीबी और एफबी ने वर्ष 2014-15 में उच्चतर वृद्धि दर्ज की।

### *ऋण - जमा अनुपात*

2.3 एससीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात पिछले वर्ष के समान लगभग 78 प्रतिशत रहा। बैंक-समूहों में, निजी क्षेत्र के बैंकों के सी-डी अनुपात में सीमांत रूप से सुधार आया जबकि अन्य घटकों में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 2.3)।

**चार्ट 2.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों, ऋणों और जमाराशियों की वृद्धि में उतार-चढ़ाव**

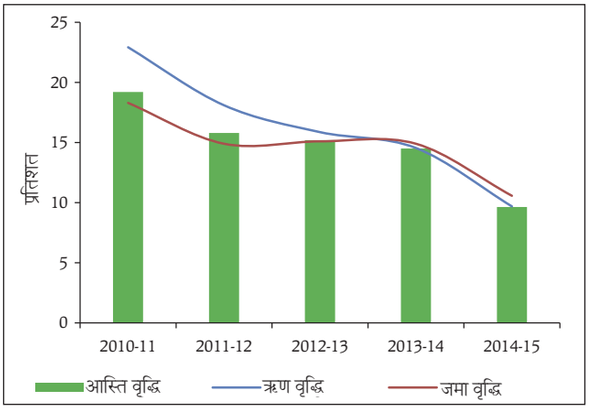


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कासा जमाराशियों में वृद्धि**

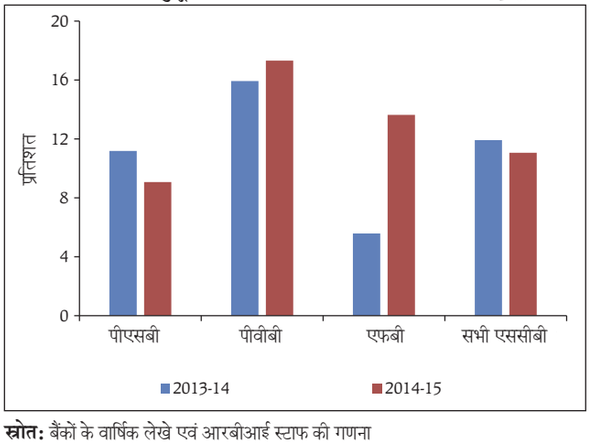


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.3 : बैंक-समूह वार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति - 31 मार्च की स्थिति**

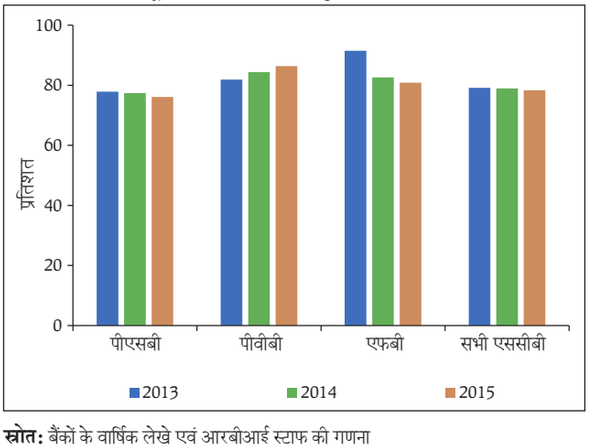


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

[1] विदेश के परिचालनों सहित।

### *देयताओं और आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल*

2.4 वर्ष 2014-15 के दौरान एससीबी की देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में सुधार देखा गया क्योंकि अल्पावधि देयताओं के अनुपात में गिरावट आई और दीर्घावधि देयताओं के अनुपात में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, दीर्घावधि आस्तियों का हिस्सा घटा और अल्पावधि आस्तियों का हिस्सा सीमांत रूप से बढ़ा (चार्ट 2.4)। इसे अनर्जक ऋणों के बढ़ते हिस्से की पृष्ठभूमि में बैंकों की जोखिम विमुखता के तौर पर देखा जा सकता है। दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का अनुपात पिछले वर्ष के 28.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 27.3 प्रतिशत रहा।

2.5 तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसबी के निवेश का 52 प्रतिशत 5 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की श्रेणी में था जबकि इस श्रेणी में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का कुल निवेश क्रमशः 30.4 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत रहा।

### *तुलन-पत्रेतर परिचालन*

2.6 बैंकों की तुलन-पत्रेतर देयताओं (अनुमानित) में, बैंकों के तुलन-पत्र परिचालनों की वृद्धि में कमी तथा पिछले वर्ष की उत्साहहीन वृद्धि के उपरांत थोड़ी समुत्थान-शक्ति देखी गई। ऐसा बकाया वायदा विनिमय संविदा से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं के कारण हुआ था, जिसका बैंकों के तुलन-पत्रेतर परिचालनों में सर्वाधिक हिस्सा था (चार्ट 2.6)। बैंक समूह-वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विदेशी बैंकों का अन्य बैंक समूहों की तुलना में वायदा संविदाओं, गारंटियों और स्वीकृति/पृष्ठांकनों में अधिकाधिक एक्सपोज़र के कारण तुलन-पत्र देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र (अनुमानित) काफी अधिक रहा।

### *एससीबी का वित्तीय कार्य-निष्पादन*

2.7 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय दोनों में कम वृद्धि दर्ज की गई। ब्याज से होने वाली आय से धीमी ऋण वृद्धि के प्रभाव का पता चलता है। तथापि, ब्याज से आय में ब्याज पर व्यय की तुलना में थोड़ी अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। परिणामस्वरूप, परिचालन व्यय में सुधार होने के बावजूद ब्याज से निवल आय में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई (वेतन बिल की वृद्धि में कमी के माध्यम से)। दूसरी ओर, बकाया ऋणों के कारण प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि की गति में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इसके

**चार्ट 2.4 : आस्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल की प्रवृत्ति**

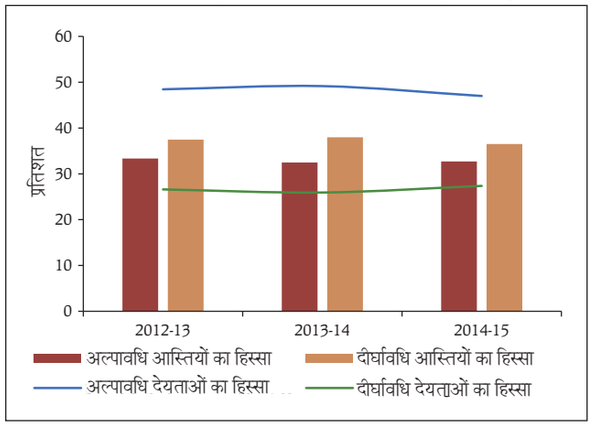


**टिप्पणी:** 1 वर्ष तक की परिपक्वता अल्पावधि कहलाती है, जबकि 3 वर्ष से अधिक परिपक्वता दीर्घावधि कहलाती है।
**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.5 : एससीबी की चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल**

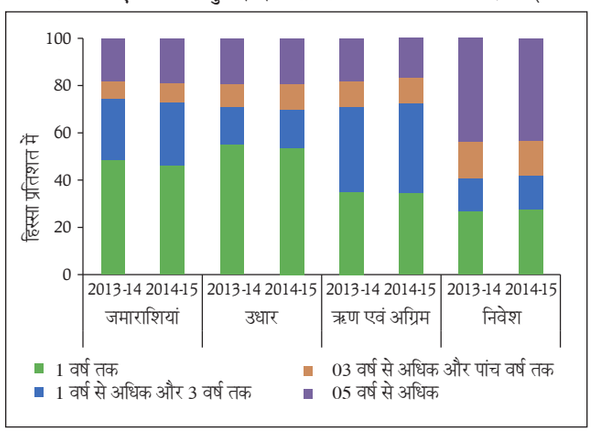


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.6: एससीबी की तुलन-पत्रेतर देयताओं की संरचना एवं वृद्धि**

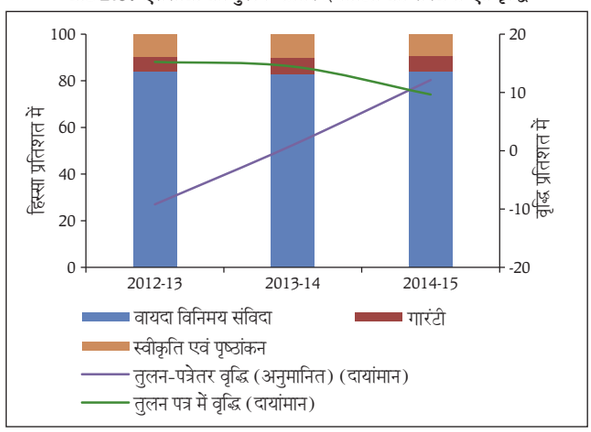


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष के दौरान निवल लाभ में आई गिरावट की तुलना में वर्ष 2014-15 में समग्र स्तर पर निवल लाभ में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 2.7)।

2.8 हाल के दिनों की प्रवृत्ति के अनुरूप, निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और स्प्रेड (निधि लागत और प्रतिलाभ के बीच अंतर) दोनों में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट 2.8)।

2.9 वर्ष 2014-15 के दौरान, आरओए पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा, फिर भी, इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) सीमांत रूप से घटा (सारणी 2.1)। बैंक-समूह स्तर पर, पीएसबी का आरओए घटा जबकि पीवीबी और एफबी का बेहतर हुआ।

### *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण*

2.10 समग्र प्रवृत्ति के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण वृद्धि में भी वर्ष 2014-15 के दौरान गिरावट आई (चार्ट 2.9) और यह गिरावट सभी उप क्षेत्रों में देखी गई और इस प्रकार कृषि के ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 30.2 प्रतिशत से गिरकर 12.6 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान, पीएसबी, पीवीबी और एफबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण क्रमशः 38.2 प्रतिशत, 43.2 प्रतिशत और 32.2 प्रतिशत था (समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो)। इस प्रकार पीएसबी द्वारा प्रदत्त

**चार्ट 2.7 : आय और व्यय की चुनिंदा मदों में वृद्धि**

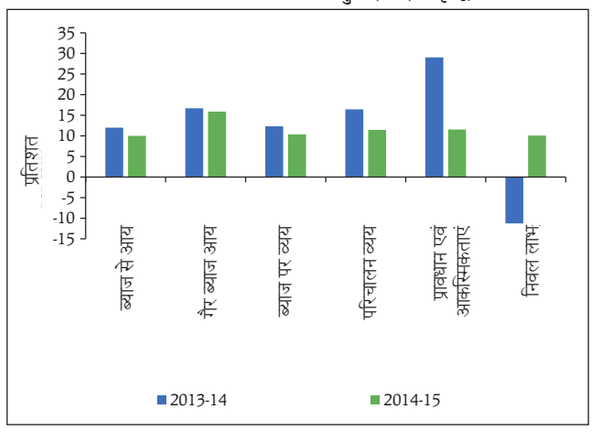


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.8 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन**

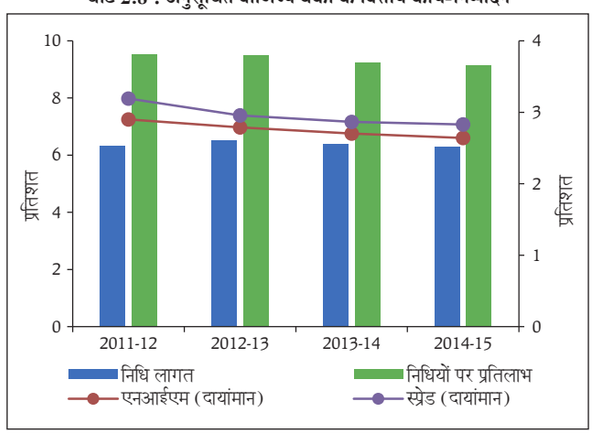


**टिप्पणियां:** निधि लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधार पर प्रदत्त ब्याज)/(चालू और गत वर्ष की जमाराशियों एवं उधार का औसत)।
निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों से अर्जित आय+ निवेश से अर्जित आय)/ (चालू और गत वर्ष के अग्रिमों एवं निवेश का औसत)।
निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय/ औसत कुल आस्तियां।
स्प्रेड = निधियों पर प्रतिलाभ और निधि लागत के बीच अंतर
**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

**सारणी 2.1 : एससीबी के आरओए एवं आरओई – बैंक-समूहवार**

(प्रतिशत)

| क्रम सं | बैंक समूह | आस्तियों पर प्रतिलाभ | | इक्विटी पर प्रतिलाभ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 |
| 1 | सरकारी क्षेत्र के बैंक | 0.50 | 0.46 | 8.47 | 7.76 |
| | 1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक* | 0.45 | 0.37 | 7.76 | 6.44 |
| | 1.2 स्टेट बैंक समूह | 0.63 | 0.66 | 10.03 | 10.56 |
| 2 | निजी क्षेत्र के बैंक | 1.65 | 1.68 | 16.22 | 15.74 |
| 3 | विदेशी बैंक | 1.54 | 1.87 | 9.03 | 10.24 |
| **4** | **सभी एससीबी** | **0.81** | **0.81** | **10.68** | **10.42** |

**टिप्पणियां:** आस्तियों पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/औसत कुल आस्तियां।
इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल इक्विटी।
*राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल हैं।
**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

ऋण 40 प्रतिशत[2] के कुल लक्ष्य से कम रहा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत पीएसबी (16.5 प्रतिशत) और पीवीबी (14.8 प्रतिशत), दोनों, द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम 18 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा।

### *खुदरा ऋण*

2.11 बैंकों की कुल ऋण वृद्धि में कमी आने के बावजूद वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि जारी रही। आवास ऋण (कुल बकाया खुदरा ऋणों का लगभग आधा हिस्सा) और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। ऑटो-ऋणों में भी सुधार देखा गया।

### *संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण*

2.12 पूंजी बाजार, भू-संपदा बाजार एवं पण्य बाजार को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की अंतर्निहित आस्तियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का बैंकों की आस्ति गुणवता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष 2014-15 में, बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदत्त कुल ऋण और अग्रिम 18.5 प्रतिशत रहा। इन संवेदनशील क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक उधार भू-संपदा बाजार को प्रदान किया गया। फिर भी, समग्र प्रवृत्ति के समान, संवेदनशील क्षेत्रों की ऋण वृद्धि में भी भू-संपदा बाजार को दिए जाने वाले उधार की वृद्धि में कमी के कारण गिरावट दर्ज की गई।[3] तथापि, 2014-15 के दौरान पूंजी बाजार को दिए गए उधार में उच्चतर वृद्धि हुई। बैंक-समूह स्तर पर, दोनों क्षेत्रों में, एफबी का एक्सपोज़र सर्वाधिक था और उसके बाद निजी क्षेत्रों का (चार्ट 2.11)।

### *एससीबी के स्वामित्व का स्वरूप*

2.13 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के हिस्से में क्रमिक गिरावट के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में पीएसबी का 72.1 प्रतिशत हिस्सा था, जो दर्शाता है कि देश में बैंकिंग क्षेत्र मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में ही रहा। तथापि, कुल आस्तियों में पर्याप्त हिस्सा होने के बावजूद, 2014-15 के दौरान कुल लाभ में पीएसबी का योगदान केवल

**चार्ट 2.9 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कुल ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति**

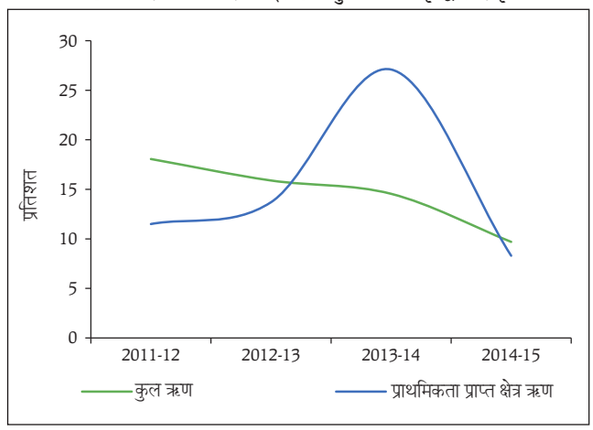


**स्रोत:** आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी और आरबीआई स्टाफ की गणना

**चार्ट 2.10 : खुदरा ऋणों में वृद्धि**

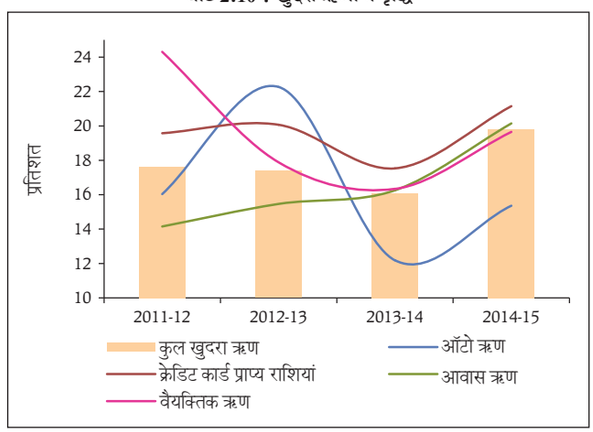


**स्रोत:** आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी

**चार्ट 2.11 : संवेदनशील क्षेत्रों को उधार का हिस्सा**

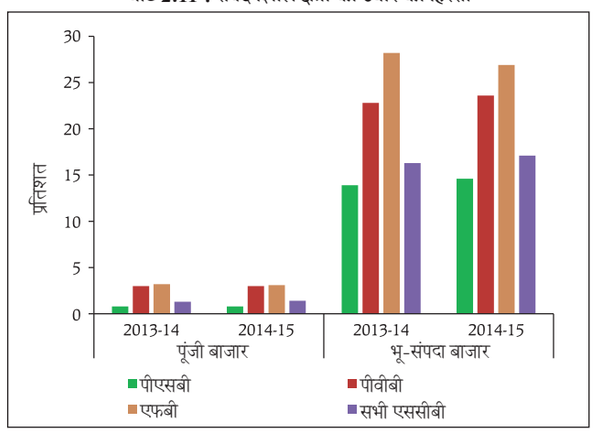


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे और आरबीआई स्टाफ की गणना

[2] विदेशी बैंकों के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य एएनबीसी अथवा तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की समतुल्य ऋण राशि, जो कोई भी अधिक हो, का 32 प्रतिशत है।

[3] कृपया *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, 2014-15* की सारणी 9 देखें।

42.1 प्रतिशत ही था एवं साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के कुल लाभ में पीवीबी का योगदान पीएसबी से बढ़ गया (चार्ट 2.12)।

2.14 पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी में आई गिरावट के बावजूद पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक रही। पीएसबी के मामले में अधिकतम विदेशी शेयरधारिता मार्च 2015 के अंत में लगभग 17 प्रतिशत थी (रिज़र्व बैंक के विनियमों के अंतर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है)। पीवीबी के मामले में अधिकतम अनिवासी शेयरधारिता 73.4 प्रतिशत थी (रिज़र्व बैंक के विनियमों के अंतर्गत अधिकतम 74 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है)।[4]

**चार्ट 2.12: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा - 31 मार्च की स्थिति**

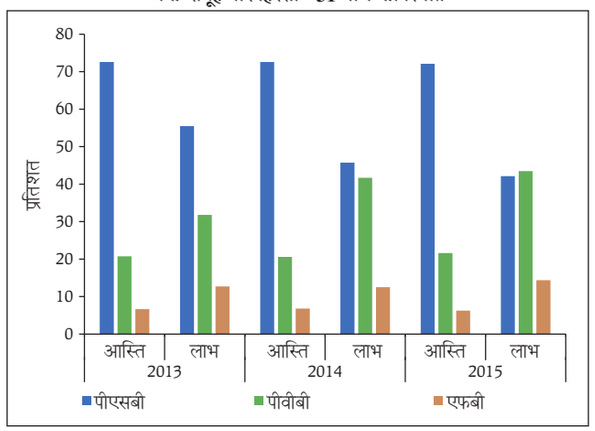


**स्रोत:** बैंकों के वार्षिक लेखे

### *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)*

2.15 समामेलन के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान आरआरबी की संख्या 57 से घटकर 56 हो गई। एससीबी की प्रवृत्ति के अनुरूप, आरआरबी के ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में भी पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 के दौरान 11.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निवेश में भी धीमी वृद्धि दर्ज की गई। देयताओं में, जमा की वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत पर एकसमान रही।

2.16 वर्ष 2014-15 के दौरान, आरआरबी की ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय, दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई जिसमें से ब्याज से आय की वृद्धि में अधिक गिरावट दर्ज की गई। इसके कारण निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सीमांत रूप से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, 2014-15 में आरआरबी की लाभ वृद्धि पिछले वर्ष के 18.5 प्रतिशत की तुलना में तेजी से घटकर 1.9 प्रतिशत रह गई। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान आरआरबी के आरओए में गिरावट आई (चार्ट 2.13)।

**चार्ट 2.13 : आरआरबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन**

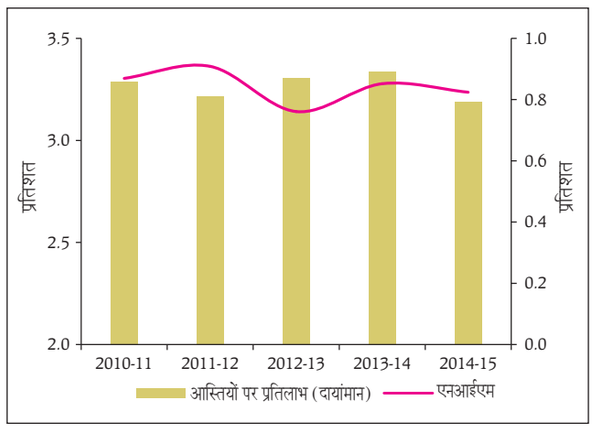


**स्रोत:** नाबार्ड

### *स्थानीय क्षेत्र बैंक*

2.17 स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की स्थापना वर्ष 1996 में दो या तीन निकटवर्ती जिलों के अधिकार-क्षेत्र के साथ स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बचत को संग्रहित कर उसे स्थानीय क्षेत्र में निवेश

[4] *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, 2014-15* की सारणी 15 देखें।

के लिए उपलब्ध करवाने हेतु निजी क्षेत्र के स्थानीय बैंकों के रूप में की गई थी। वर्तमान में, चार एलएबी परिचालन में है। इनमें से, मार्च 2015 की समाप्ति पर एलएबी की कुल आस्तियों में से 72.9 प्रतिशत कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के पास था।

2.18 वर्ष 2014-15 के दौरान एलएबी की आस्तियों में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ब्याज से निवल आय में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि आरओए में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 2.14)।

2.19 कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु रिज़र्व बैंक से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त होने पर कुल बैंकिंग आस्तियों में एलएबी के शेयर में और गिरावट आएगी।

### *ग्राहक सेवा*

2.20 वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त शिकायतों में 70 प्रतिशत से अधिक पीएसबी से संबंधित थी और सभी प्रमुख श्रेणियों में, पीएसबी का शेयर 60 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त 25 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पीवीबी से संबंधित थीं (चार्ट 2.15)।

## अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

### *एटीएम की संख्या में वृद्धि*

2.21 बैंकों ने वर्ष 2015 में कुल 0.18 मिलियन एटीएम के साथ अपनी पहुंच को और बढ़ाया। तथापि, पीएसबी और पीवीबी, दोनों क्षेत्र के बैंकों की एटीएम वृद्धि में कमी आई। पीएसबी ने 2014-15 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसका कुल एटीएम में लगभग 70 प्रतिशत

**चार्ट 2.14 : एलएबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन**

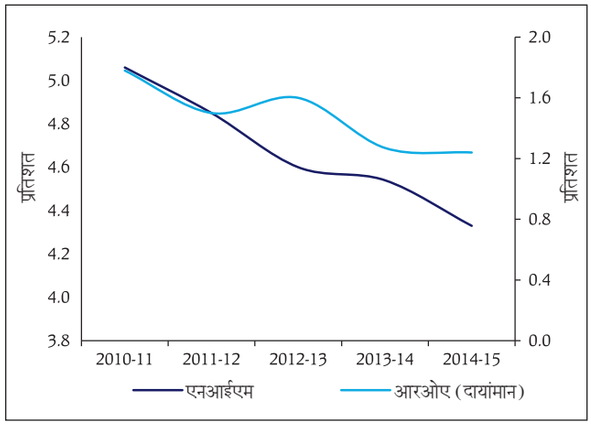


**स्रोत:** आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी

**चार्ट 2.15 : मुख्य शिकायतों के प्रकार का बैंक-समूह वार अलग-अलग विवरण: 2014-15**

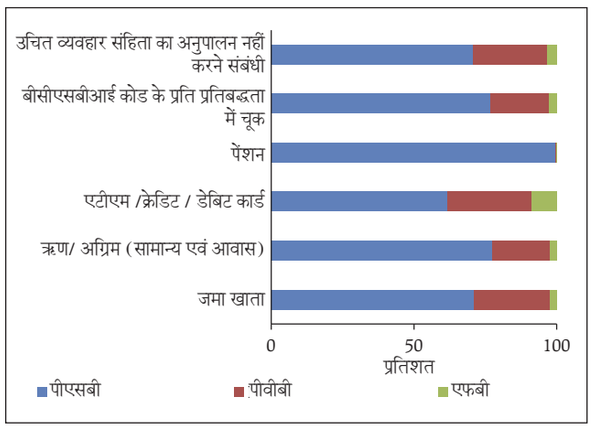


**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट 2.16: एटीएम की वृद्धि और संरचना**

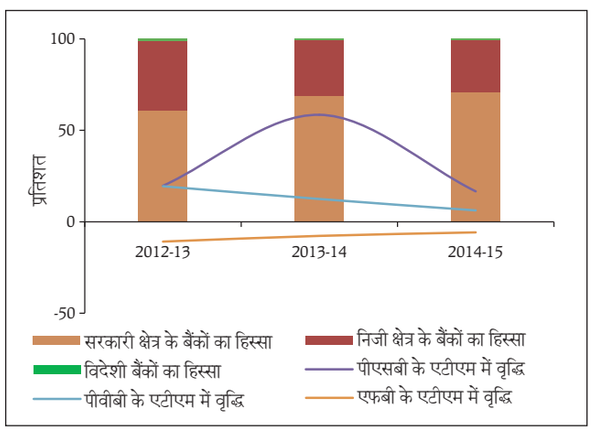


**स्रोत:** आरबीआई

हिस्सा रहा। एफबी के एटीएम में लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुई (चार्ट 2.16)।

### *जनसंख्या समूह-वार एटीएम का वितरण*

2.22 हाल के वर्षों में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के एटीएम में लगातार वृद्धि हो रही है, यद्यपि शहरी और महानगरीय केंद्रों का प्रभुत्व जारी है। 2015 में, लगभग 44 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों पर स्थित थे (चार्ट 2.17)।

### *ऑफ-साइट एटीएम*

2.23 मार्च 2015 की समाप्ति पर कुल एटीएम में ऑफ-साइट एटीएम का शेयर पिछले वर्ष के 47.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 50.9 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऑफ साइट एटीएम के शेयर में हुई वृद्धि ने मुख्य भूमिका अदा की है जिसका शेयर वर्ष 2014 के 40.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 45.7 प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों का शेयर पहले ही 60 प्रतिशत से अधिक था (चार्ट 2.18)।

### *व्हाइट लेबल एटीएम*

2.24 ऑफ-साइट एटीएम की दक्षता और लागत-प्रभावकारिता को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2012 में गैर-बैंक संस्थाओं को एटीएम लगाने और परिचालन करने की अनुमति प्रदान की थी जिन्हें 'व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)' कहा जाता है। 31 अक्तूबर 2015 तक कुल 10,983 डब्ल्यूएलए स्थापित की गई थीं।

### *डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड*

2.25 क्रेडिट कार्ड की तुलना में कही अधिक संख्या में डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं और वे अंतरण का मुख्य माध्यम बने हुए हैं। 2012 में प्रत्येक 100 डेबिट कार्ड की तुलना में 6.43 क्रेडिट कार्ड थे जो 2015 में घटकर 3.8 रह गए (चार्ट 2.19)। डेबिट कार्ड जारी करने में पीएसबी ने पीवीबी और एफबी पर बढ़त बना रखी है। 31 मार्च 2015 को लगभग 83 प्रतिशत डेबिट कार्ड पीएसबी द्वारा जारी किए गए थे, जबकि लगभग 80 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड पीवीबी (57.2 प्रतिशत) और एफबी (22.4 प्रतिशत) द्वारा जारी किए गए थे।

### *प्रीपेड भुगतान लिखत*

2.26 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) ऐसे भुगतान लिखत हैं जो इस प्रकार के लिखतों में डाले गए मूल्य के बराबर निधि अंतरण सहित

**चार्ट 2.17: एटीएम का भौगोलिक वितरण**

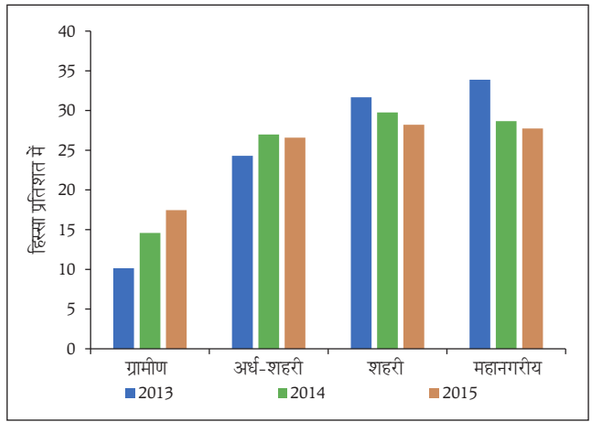


**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट 2.18 : ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा**

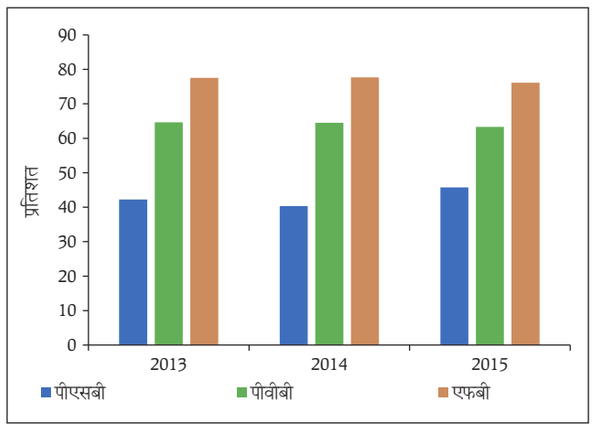


**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट 2.19 : डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करना**

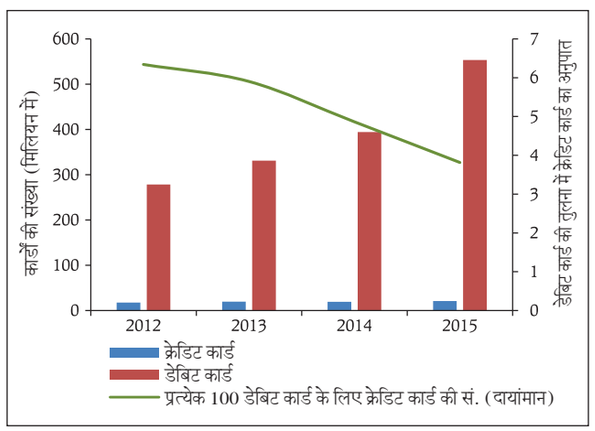


**स्रोत:** आरबीआई

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। इन लिखतों में डाला गया मूल्य, धारक द्वारा नकदी, बैंक खाते में डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए मूल्य को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, पीपीआई कम मूल्य के दैनंदिन भुगतान अंतरणों के लिए नकदी के एक आसान विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पीपीआई का मूल्य 2012-13 के 79.2 बिलियन रुपए से बढ़कर 2014-15 में 213.4 बिलियन रुपए हो गया है। पीपीआई लिखतों में, पीपीआई कार्ड सबसे अधिक लोकप्रिय रहा (चार्ट 2.20)। इस वृद्धि को, सबसे अधिक गैर बैंक पीपीआई ने गति प्रदान की है।

**चार्ट 2.20 : प्रीपेड लिखतों की प्रगति (मूल्य)**

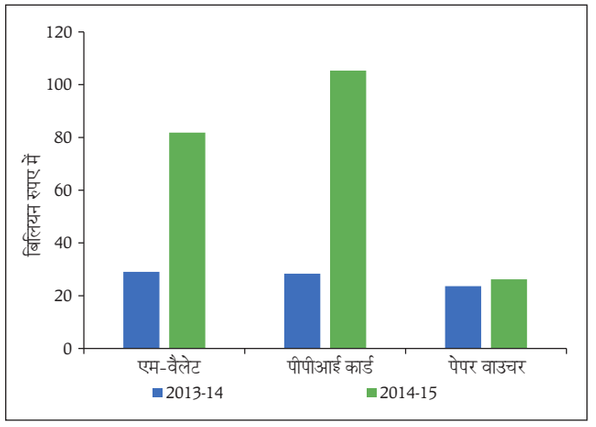


**स्रोत:** आरबीआई

## वित्तीय समावेशन के प्रयास

2.27 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से मिले प्रोत्साहन से बैंकिंग की पहुंच में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, काफी संख्या में बैंकिंग आउटलेट, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ सुलभकर्ताओं के माध्यम से शाखारहित मोड में परिचालन करते हैं (चार्ट 2.21)। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी के प्रभुत्व को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को लगभग 91 प्रतिशत बैंकिंग आउटलेट शाखारहित मोड में परिचालन कर रहे थे।

**चार्ट 2.21 : बैंकिंग आउटलेट और बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) की प्रगति**

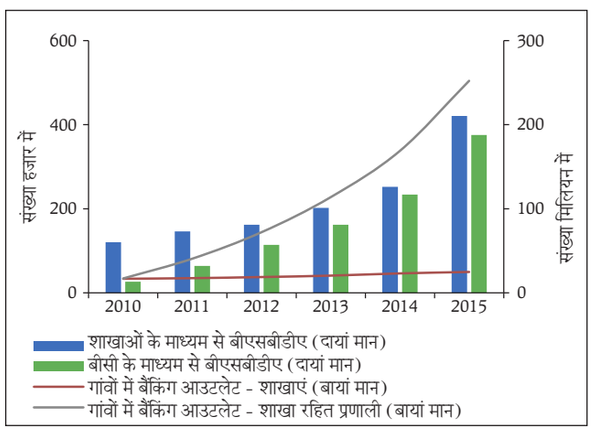


**स्रोत:** आरबीआई

2.28 09 दिसंबर 2015 तक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 195.2 मिलियन खाते खोल जा चुके हैं और 166.7 मिलियन रूपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने, सभी परिवारों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंकिंग खाता खोलने तथा रूपे डेबिट कार्ड प्रदान करने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने, क्रेडिट गारंटी निधि, माइक्रो-बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इन उद्देश्यों के, चार वर्ष की अवधि के दौरान अगस्त 2018 तक दो चरणों में पूरे होने की संभावना है। बैंकों को ग्रामीण एटीएम के संबंध में रिज़र्व बैंक की सब्सिडी योजना का लाभ उठाने की भी अनुमति दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगुवाई में वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के उद्देश्य एक-दूसरे के समनुरूप हैं।

2.29 वित्तीय समावेशन के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने और देश में बीमा और पेंशन की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मई 2015 में कई सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरूआत की है। 16 दिसंबर 2015 को 92.6 मिलियन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन करवाया है और 29.2 मिलियन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करवाया है। इसके अतिरिक्त, 1.3 मिलियन खाताधारकों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन करवाया है।